

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 07 जुलाई, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद के ग्राम कासमपुर में राजकीय इण्टर कालेज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्रांक-220/नि.स.क./एम.एस.डी.पी./Budget-released/2015-16 दिनांक 23.05.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-3/20(4)/2013-PP-I दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 की तालिका-(a) के क्रमांक-1 पर जनपद हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद के कासमपुर में राजकीय इण्टर कालेज के भवन निर्माण हेतु कुल अनुमोदित धनराशि ₹ 378.45 लाख के सापेक्ष 75% केन्द्रांश ₹ 283.8375 लाख में से प्रथम किश्त की अवशेष 25 % धनराशि के रूप में ₹ 70.96 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पूर्व पत्र संख्या-3/20(4)/2013-PP-I दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा उक्त कार्य योजना हेतु प्रथम किश्त की 25 % स्वीकृत धनराशि के क्रम शासन के पत्र संख्या-290, दिनांक 30 मार्च, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त की 25 % धनराशि (₹ 70.96 लाख केन्द्रांश + ₹ 23.65 लाख राज्यांश) कुल धनराशि ₹ 94.61 लाख (चौरानवे लाख इकसठ हजार मात्र) जारी की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किश्त की अवशेष 25 % धनराशि ₹ 70.96 लाख केन्द्रांश + ₹ 23.6525 लाख राज्यांश अर्थात् कुल धनराशि ₹ 94.6125 लाख (₹ चौरानवे लाख इकसठ हजार दो सौ पचास मात्र) की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये। उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र, दिनांक 21.04.2015 द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं एम0एस0डी0पी0 की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय के अंतर्गत भवन कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये।
3. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्ज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। कार्य हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के पूर्व संतोषजनक व्यय विषयक आख्या प्राप्त होने पर ही वर्तमान में स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।
5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। आंगणन में प्राविधानित व्यय करने से पूर्व उक्त हेतु उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से की गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
7. एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
10. यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।
11. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
12. स्वीकृत उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व, प्रश्नगत योजना हेतु भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करनी आवश्यक होगी। किसी भी दशा में भूमि उपलब्ध न होने पर उक्त स्वीकृत धनराशि जारी न की जाय।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ-01-अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टरल विकास योजना के मानक मद-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
14. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं शासनादेश संख्या:-645/XXVII(1)/2015, दिनांक 04 जून, 2015 में निहित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
15. यह आदेश अलोटमेंट आई.डी. संख्या-S1507150013, दिनांक 01 जुलाई, 2015 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:-1040(1)/XVII-3/15-07(6-MSDP)/2015 : तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. महाप्रबन्धक, उ०प्र०रा० निर्माण निगम लि०, ई० 34 नेहरू कॉलोनी देहरादून।
6. नोडल अधिकारी/उप सचिव (एम०एस०डी०पी०), उत्तराखण्ड शासन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
9. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,


(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।